राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3374/2024

कालू राम मेनारिया पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल मेनारिया, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी 388 पानेरियों की मादड़ी, वाटर टैंक के पास, जिला उदयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. किरण कोठारी पत्नी श्री अनूप कोठारी, निवासी 6 न्यू पोलो ग्राउंड, उदयपुर।

---प्रतिवादी

एस.बी. से जुड़े आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3371/2024

कालू राम मेनारिया पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल मेनारिया, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी 388 पानेरियों की मादड़ी, वाटर टैंक के पास, जिला उदयपुर ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. अनूप कोठारी पुत्र श्री शांति लाल कोठारी, निवासी 8, न्यू पोलो ग्राउंड, उदयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री नरेश सिंह, श्री राकेश अरोड़ा के लिए

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री श्री राम चौधरी, पीपी.

आर.सं.2 के लिए श्री विवेक फिरोदा

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

22/08/2024

1. इस सामान्य आदेश के तहत उपर्युक्त दोनों याचिकाओं का निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि न केवल तथ्य समान हैं, बल्कि इनमें उठाए गए मुद्दे भी समान हैं। संक्षिप्तता के लिए, एस.बी. आपराधिक विविध याचिका संख्या 3374/2024 से उद्धरण लिए गए हैं।

2. याचिकाकर्ता यहां विद्वान विशेष न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा पारित दिनांक 06.05.2024 (अनुलग्नक 4) के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने 65 लाख रुपये के चेक के अनादर के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, उत्तर संख्या 1, उदयपुर के समक्ष याचिकाकर्ता के विरुद्ध परक्राम्य

लिखत अधिनियम (संक्षेप में "एन.आई. अधिनियम") की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई।

3.1. परिवादी-प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं को पी.डब्लू./1 के रूप में परीक्षित किया, यद्यपि एन.आई. अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत अपेक्षित कोई शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया। तथापि, वह स्वयं विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तथा उसके मुख्य परीक्षण का कथन भी मौखिक रूप से दर्ज किया गया। साथ ही, उसने जो दस्तावेज प्रदर्शित करने चाहे, वे उसके मुख्य परीक्षण के दौरान प्रदर्श पी/1 से पी/13 के रूप में प्रदर्शित किए गए।

3.2. समय के साथ, सुनवाई पूरी होने के बाद, विद्वान निचली अदालत ने दिनांक 12.01.2023 के निर्णय के तहत याचिकाकर्ता को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.01.2023 के निर्णय के खिलाफ अपील पेश की, जो कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, उदयपुर के समक्ष विचाराधीन है। अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने 02.05.2024 को एन.आई. एक्ट की धारा 145 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें शिकायतकर्ता से जिरह करने की अनुमति मांगी गई, जिसे विद्वान अपीलीय अदालत ने दिनांक 06.05.2024 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा संबोधित प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

5. विवादित आदेश अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क पर आधारित है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 के अनुसार साक्ष्य हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" है न कि "करेगा"। इसका अर्थ है कि न्यायालय हलफनामे के माध्यम से

शिकायतकर्ता की मुख्य परीक्षा ले सकता है या न्यायालय शिकायतकर्ता के उपस्थित होने पर उसका मौखिक साक्ष्य दर्ज कर सकता है। अपीलकर्ता-आरोपी ने अपने आवेदन के माध्यम से एक और आपत्ति उठाई, जिसमें कहा गया कि केस फाइल पर मौजूद दस्तावेजों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। हालांकि, यह तर्क भी उचित नहीं लगता, क्योंकि केस फाइल के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीठासीन अधिकारी ने उन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. मुझे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं दिखती। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 में निम्नलिखित प्रावधान है:

> <u>145. हलफनामे पर साक्ष्य:</u>
>
> (1). दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, शिकायतकर्ता का साक्ष्य शपथ पत्र पर दिया जा सकता है और सभी उचित अपवादों के अधीन रहते हुए, उक्त संहिता के अंतर्गत किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।
>
> (2). न्यायालय, यदि वह उचित समझे, अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के आवेदन पर, शपथ पत्र में निहित तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को बुला सकता है और उसकी जांच करेगा।

6.1. मेरी राय में, धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति का है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विवादित आदेश में सही टिप्पणी की है कि यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इस प्रकार विवादित आदेश सही तरीके से पारित किया गया। इसलिए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6.1. मेरी राय में, धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति का है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विवादित आदेश में सही टिप्पणी की है कि यह अनिवार्य प्रावधान नहीं है। इस प्रकार विवादित आदेश सही तरीके से पारित किया गया था। इसलिए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. इसके अलावा, यह पता चला है कि बाद में, याचिकाकर्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 के तहत एक और आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक कानून के कथित उल्लंघन के कुछ दावों का दावा किया गया था, और इस प्रकार, यह तर्क दिया गया था कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

8. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता के लिए यह उचित था कि वह प्रक्रियात्मक उल्लंघन की आपत्तियों को प्रासंगिक समय पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाता, न कि उन्हें बाद में विचार करके विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विद्वान अपीलीय कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करके उठाता।

9. जैसा भी हो, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक कानून के कथित उल्लंघन की दलीलों को विद्वान अपीलीय कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही में तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

10. मेरा विचार है कि अपीलकर्ता की टालमटोल की रणनीति को देखते हुए, मुकदमे के समापन में 10 साल से अधिक का समय लग गया और उसके बाद, अपीलकर्ता को कई अवसर दिए जाने के बावजूद उसकी अपील में दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

11. याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए, वह इन याचिकाओं में किसी भी तरह की छूट का हकदार नहीं है।

12. खारिज।

13. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, निपटाए जाएँगे।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।